RNI No.: DEL/BIL/2004/14598

Youngster

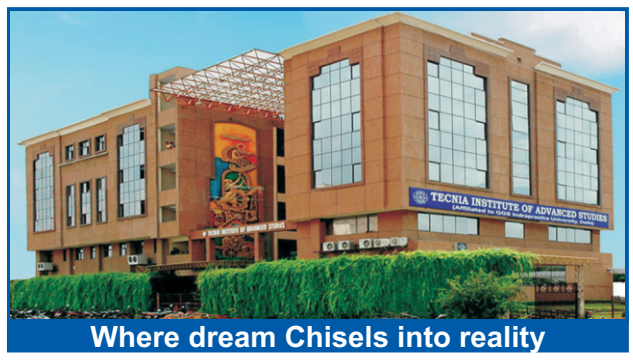

YOUNGSTER · ESTABLISHED 2004 · NEW DELHI · JUNE 2021 · PAGES 4 · PRICE 1/- · MONTHLY BILINGUAL (HIN./ENG.)

टीकाकरण अभियान की गति और तेज होने से अर्थव्यवस्था भी जल्द ही पटरी पर लौटेगी

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा देश में कोरोना महामारी के बचाव के लिए 24 घंटे सातों दिन टीका लगाये जाने की व्यवस्था कुछ ही समय में विकसित किए जाने की अनुशंसा की है ताकि टीका लगाए हुए लोगों के दायरे को बढ़ाते हुए देश की अर्थव्यवथा को पुनः तेजी से दौड़ाया जा सके। हाल ही में जारी किए गए अपने मासिक प्रतिवेदन में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि देश में झुंड प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए 70 करोड़ युवाओं को टीके की कम से कम खुराक 30 सितम्बर 2021 के पूर्व लगाई जाना अत्यंत आवश्यक है। इससे देश के उपभोक्ता एवं उत्पादकों में आत्मविश्वास का स्तर बढ़ेगा एवं यह आर्थिक विकास को शीघ्र ही गति देने में सहायक सिद्ध होगा। इसका आशय यह है कि अगले केवल लगभग 3.5 माह के दौरान लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रतिदिन टीका देना होगा तभी उक्त लक्ष्य को 30 सितम्बर 2021 तक हासिल किया जा सकता है।

देश में आज की परिस्थितियों में देशवासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए उन्हें टीका लगाना ही एकमात्र उपाय उपलब्ध है। कोरोना महामारी की प्रथम लहर के बाद भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो रही थी कि अचानक दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था को पुनः एक झटका दे दिया। स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था दोनों ही नजरियों से टीका ही एक उपाय के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। टीका लगाने से कोरोना महामारी से बचा जा सकता है अथवा यदि कोरोना से संक्रमण होता भी है तो यह उतना गंभीर नहीं होगा कि संक्रमित व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए। देश की कुल जनसंख्या के एक बहुत बड़े वर्ग का टीकाकरण कर लिया जाये अब इस ओर केंद्र सरकार द्वारा गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। इससे देश में कोरोना से लड़ाई के विरुद्ध आत्मविश्वास पैदा होगा। लोग बगैर किसी डर के घरों से बाहर निकल सकेंगे और इससे बाजारों में रौनक पुनः लौट सकती है। देश की बड़ी आबादी पर्यटन के लिए अपने शहरों से बाहर जा सकती हैं। निर्माण उद्योग भी पुनः अपने उच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है इससे पर्यटन एवं निर्माण के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इन्हीं कारणों से केंद्र सरकार का सोचना है कि 30 सितम्बर 2021 के पूर्व देश में 70 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर लिया जाये। केंद्र सरकार ने, टीका उत्पादकों से चर्चा करने के उपरांत, ताकि आगे आने वाले समय में टीकों की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की परेशानी खड़ी न हो, अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए राज्य सरकारों का भी सहयोग लिया जा रहा है। अब टीकों की उत्पादकों से अभिप्राप्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी इससे राज्य सरकारों पर दबाव कम होगा और राज्य सरकारें केवल टीकाकरण की ओर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। टीकाकरण का पूरा खर्च भी अब केंद्र सरकार द्वारा ही वहन किया जायेगा।

टीकों का निर्माण करने वाली कम्पनियों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए टीकों के निर्माण को बढ़ाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। साथ ही अन्य देशों में टीकों का निर्माण करने वाली कम्पनियों को भी भारत में ही इन टीकों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब टीकों का निर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा निर्मित किए गए 100 टीकों में से 75 प्रतिशत टीके केंद्र सरकार द्वारा खरीदे जाएंगे एवं शेष 25 प्रतिशत टीके इन कम्पनियों द्वारा बाजार में बेचा जा सकेगा। इससे इन कम्पनियों को यह निश्चिंतिता रहेगी कि उनके द्वारा उत्पादित टीकों का 75 प्रतिशत भाग तो तुरंत ही बिक जाएगा।

ग्रामीण इलाकों को भी टीकाकरण के दायरे में लाकर ग्रामीणों का टीकाकरण तेजी से हो इस हेतु प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने ग्रामीणों को भी प्रभावित किया है। इस तरह से कुल मिलकर सभी मोर्चों पर कार्य किया जा रहा है। देश में सभी समाजों एवं निजी क्षेत्र को भी इस काम में मदद करने हेतु निवेदन किया जा रहा है। अकेले केंद्र सरकार यह इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकती है। टीकों के निर्माण, अभिप्राप्ति के साथ–साथ टीकों के वितरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी राज्य में टीकों की उपलब्धता पर कोई विपरीत असर नहीं पड़े। दूरदराज ग्रामीण इलाकों में भी टीका समय पर उपलब्ध रहे इस हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। लक्ष्य बहुत ही बड़ा है परंतु देश में इस समय इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। अभी लगभग 30 लाख टीके प्रतिदिन लगाए जा रहे हैं इसे बढ़ाकर एक करोड़ से अधिक टीके प्रतिदिन तक ले जाना है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए यह कार्य तो करना ही होगा।

सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं एवं अन्य सेवाओं में कार्यरत लोगों को टीका लगाया गया इसके बाद 60 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को और अब 18 वर्ष से अधिक की आयु का लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोरोना महामारी के समय में अस्पतालों में टीका लगाने वाले लोगों की भीड़ नहीं हो। हालांकि कोरोना के संक्रमण के धीरे–धीरे कम होने के साथ ही अब कुछ जगह पर वॉक–इन टीका लगने का काम भी शुरू किया जा चुका है। अब तो धीरे–धीरे और भी छूट दी जा सकती है जैसे पंजीकरण कराने के बाद अब कहीं भी और कभी भी टीका लगवाया जा सकता है। अब टीका लगाने की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया जा रहा है। शुरुआत में जरूर कुछ नियम बनाए गए थे ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे।

भारत में आज डिजिटल, संप्रेषण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत हो गई है अतः देश में इस प्रणाली का भी पूरा–पूरा लाभ लिया जा सकता है। भारत में अपार क्षमताएं एवं सम्भावनाएं मौजूद हैं जिनका पूरा उपयोग करते हुए प्रतिदिन एक करोड़ लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। टीकाकरण के कार्यक्रम में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल भी किया जा रहा है और पंजीकरण कराने के साथ ही टीका लगे हुए व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है।

अब तो कोरोना महामारी का दूसरा दौर ढलान पर है एवं देश में टीकाकरण के कार्य में भी तेजी लायी जा रही है ऐसे में अब केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपने पूंजीगत ख़र्चों में वृद्धि करनी चाहिए ताकि रोजगार के नए अवसर निर्मित हों और उत्पादित वस्तुओं की मांग पैदा हो। इससे देश के गरीब वर्ग में आत्मविश्वास पैदा होगा और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी। केवल केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें ही क्यों अब तो निजी क्षेत्र को भी आगे आना चाहिए और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहिए। आज की परिस्थितियों में अधूरी पड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता सूची में डालकर शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किए जाने चाहिए। निर्माण क्षेत्र को गति दी जानी चाहिए एवं ग्रामीण इलाकों में नए नए अस्पतालों का निर्माण भी किया जा सकता है ताकि ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो सके। इन सभी उपायों से देश की अर्थव्यवस्था में पुनः एक बार ट आकर की रिकवरी प्राप्त की जा सकती है।

कोरोना रोधी टीकों के बारे में दुष्प्रचार अकेले सरकार नहीं रोक सकती, हमें भी आगे आना होगा कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए देश को तेजी से वैक्सीन लगाने के साथ–साथ देश में वैक्सीन के बारे में किये जा रहे दुष्प्रचार से भी लड़ना होगा। आने वाली कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हम अभी से सचेत न हुए तो यह तय है कि तीसरी लहर दूसरी से भी ज्यादा भयावह और जानलेवा होगी। तीसरी लहर के प्रति केंद्र सरकार अभी से सचेत कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही आदेश दिया है। महाराष्ट्र सरकार और उसके विशेषज्ञों ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर उनके यहाँ आ गई है। केंद्र सरकार के विशेषज्ञ अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। पर लॉकडाउन खुलने के बाद देश में जिस तरह से पब्लिक सड़कों पर निकली है, यह चिंताजनक है। इसके लिए हमें आत्म नियंत्रण करना होगा। विवाह और समारोह से कुछ समय बचना होगा। जरूरी होने पर ही घर से निकलना होगा। वैक्सीनेशन पर जोर देना होगा।

हर्षित श्रीवास्तव, बीएजेएमसी तृतीय वर्ष

बैठक के जरिये मोदी जानना चाहते थे कश्मीरी नेताओं का हृदय परिवर्तन हुआ है या नहीं

कश्मीर में कुछ बड़ा करने से पहले घाटी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री द्वारा बैठक करना एक प्रयोग मात्र था, फिलहाल हाई प्रोफाइल इस बैठक से दो बातें स्पष्ट हुईं। अव्वल, बैठक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटी के विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं का मन टटोला और ये जाना कि 370 के बाद जम्मू–कश्मीर के विकास और आवाम की खुशहाली के लिए वह कितने संजीदा हैं। या फिर अपनी राजनीतिक महात्वाकांक्षाओं के लिए वैसे ही तड़फड़ा रहे हैं जैसे नजरबंदी के पूर्व थे। दूसरा, बैठक में प्रधानमंत्री और उनके मंत्री ज्यादा कुछ नहीं बोले, बोलने का मौका कश्मीरी नेताओं को ही दिया। गुपकारों ने जो पांच मांगें बैठक में रखीं, कमोबेश वह वही थीं जिस पर कभी सहमति बननी ही नहीं थी। गुपकार अलाएंस नेता इस भ्रम में रहे कि शायद केंद्र सरकार अब उनके दबाव में आ गई है। तभी कोरोना संकट के बीच उनको दिल्ली तलब किया गया। पर, शायद उन्हें पता नहीं था उनके भीतर का भेद मुलाकात के माध्यम से जानना था। उनका मन भी टटोलना था कि कश्मीरी नेताओं की सियासी महात्वाकांक्षाएँ कम हुई या अपने चिरपरिचित अंदाज में हालचाल पूछा, घर–परिवार की खैरियत जानी। उसके बाद उन्होंने कहा जी बताएं, कश्मीर के लिए क्या कुछ करना चाहिए। बस फिर क्या था, कश्मीरी नेताओं ने लगा दी मांगों की बौछारें, मांगों में ज्यादातर उनकी सियासी महात्वाकांक्षाएं जुड़ी थीं। कश्मीरियों के लिए अपने निजी स्वार्थ की बातें ज्यादा शामिल थीं। फिलहाल उनकी मांगों को केंद्रीय नेतृत्व चुपकार सुनता रहा। दरअसल, प्रधानमंत्री ने माहौल कुछ ऐसा बना दिया था, ताकि वह खुलकर अपनी इच्छा जाहिर कर सकें। मांगों का पिटारा जब घाटी के नेताओं ने खोला तो सबने अलग–अलग इच्छाएं रखीं। जम्मू–कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे ने खुलकर धारा–370 आर्टिकल 35ए की बहाली की मांग रखी। वह दोनों पहले भी इसी मांग पर जोर देते आए थे। साथ ही उन्होंने धमकीनुमा ये भी कहा कि कोर्ट में इस मसले को लेकर उनकी लड़ाई जारी रहेगी। फारूक अब्दुल्ला की धारा–370 की बहाली की मांग के बाद बैठक में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छाना स्वाभाविक भी था। क्योंकि बैठक में कश्मीर के

नहीं?

प्रधानमंत्री के साथ कश्मीरी नेताओं की करीब चार घंटे चली बैठक फिलहाल किसी नतीजे के खत्म हुई। पहले राउंड की वार्ता थी, इसलिए ज्यादा उम्मीद तो पहले से ही नहीं थी? पर, कश्मीरी नेताओं में कन्फ्यूजन जबरदस्त दिखा। बैठक में उनका जो एकजुटता दिखानी चाहिए थी, वह नहीं दिखी। राजनीतिक रूप से एकता की डोरी से कोई बंधा नहीं दिखा। सब अपना अलग–अलग राग और ढपली बजाते दिखे। सामूहिक मांग पर कोई भी टिकता नहीं दिखा। बैठक में आठ दलों के कुल 14 नेता दिल्ली बुलाए गए थे जिनमें से कुछ तो इसलिए खुश थे, उनको प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने का मौका मिल रहा था। बाकी एकाध टूटकर कुछ समय बाद मोदी के पक्ष में आ जाएंगे, चुनाव से पहले, इसकी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। सूत्र बताते भी हैं, चुनाव में घाटी के एक–दो दल भाजपा के साथ आएंगे। इसके लिए भाजपा घेराबंदी में लगी भी है।

प्रधानमंत्री ने गुपकार नेताओं और देश के लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए एक बेहतरीन प्रयोग किया। दरअसल, बैठक से पूर्व जारी की गई एक ग्रुप तस्वीर जिसको सोशल मीडिया पर सभी देशवासियों ने देखा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी गुपकार अलाएंस के नेता खड़े दिखाई दिए, वह भी बिना मास्क के, फोटो खिंचवाने के वक्त मास्क हटाने के पीछे भी कई राज छिपे थे। खैर, फोटो में अधिकांश नेताओं के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी, बस एकाध के चेहरे मुरझाए हुए थे। इसी तस्वीर को प्रधानमंत्री ने तुरंत अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। इस थ्योरी को समझने की जरूरत है। तस्वीर के जरिए ये बताना चाहा कि दोनों पक्षों में मीटिंग सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रही है। गुपकार पक्ष प्रधानमंत्री से खुश है।

बहरहाल, तस्वीर खुशनुमा वातावरण जरूर बयां कर रही थी। लेकिन कहानी उसके कहीं विपरीत थी। जब मीटिंग आरंभ हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं से भविष्य का ताना बाना बुनना था, न कि अतीत के पन्नों को कुरेदना था।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी फिर से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने पर प्रधानमंत्री पर जोर डाला। इससे बैठक में कुछ तल्खी का माहौल बना। कुल मिलाकर बैठक के जरिए प्रधानमंत्री कश्मीरी नेताओं को टोहना चाह रहे थे। वह ये जानना चाहते थे कि बीते दो वर्षों से रुकी बातचीत और नजरबंदी के बाद घाटी के नेताओं के हृदय में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं? या फिर पुरानी जहरीली सोच से ग्रसित हैं, जिसका उन्हें ठीक से आभास हो गया। मीटिंग से पता चल गया कि उनकी सोच वैसी की वैसी ही है। सच ये है कि जम्मू–कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री की रणनीति और ब्लू प्रिंट पहले से तैयार है। प्रधानमंत्री का मानना था कि अगर उनकी रणनीति में कश्मीरी नेताओं के विचार मेल खाते हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन बैठक के जरिए इतना स्पष्ट हो गया कि उनकी सोच से कश्मीरी नेता फिट नहीं बैठते? इसी बात की नब्ज टटोलने के लिए प्रधानमंत्री ने सभी को दिल्ली बुलाया था।

बहरहाल, अब जम्मू–कश्मीर के लिए जो भी करना होगा, प्रधानमंत्री आजाद होकर फैसला करेंगे, भविष्य में किसी भी फैसले में वह उनकी राय नहीं जानेंगे। क्योंकि राय जानने में सिर्फ समय बर्बाद करना होगा। बैठक से इतना पता चल गया है कि कश्मीरी नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरी बात ये कि जब दिल्ली में बैठक चल रही थी। तभी पाकिस्तान में इमरान खान बैठक कर रहे थे, उनकी नजर भी प्रधानमंत्री के फैसले पर टिकी थी। कश्मीरी नेताओं में महबूबा मुफ्ती ही एक ऐसी नेता हैं जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा याद करती हैं। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री से दोनों देशों के बीच रेलगाड़ी चलाने का भी आग्रह किया।

वंशिका सक्सेना, बीएजेएमसी तृतीय वर्ष

THIS MONTH

June 17, 1972 - Following a seemingly routine burglary, five men were arrested at the National Democratic Headquarters in the Watergate complex in Washington, D.C. However, subsequent investigations revealed the burglars were actually agents hired by the Committee for the Re-election of President Richard Nixon. A long chain of events then followed in which the president and top aides became involved in an extensive cover-up of this and other White House sanctioned illegal activities, eventually leading to the resignation of President Nixon on August 9, 1974.

*****

June 30,1971-The 26th Amendment to the U.S. Constitution was enacted, granting the right to vote in all federal, state and local elections to American citizens 18 years or older. The U.S. thus gained an additional 11 million voters. The minimum voting age in most states had been 21.

*****

June 30, 1997 - In Hong Kong, the flag of the British Crown Colony was officially lowered at midnight and replaced by a new flag representing China's sovereignty and the official transfer of power.

Compilation:
Priya

BASICS OF MEDIA

Control Room :A room adjacent to the studio in which the director, the technical director, the audio engineer, and sometimes the lighting director perform their various production functions.

*****

Medium Requirements: All content elements, production elements, and people needed to generate the defined process message.

*****

Program Speaker: A loudspeaker in the control room that carries the program sound. Its volume can be controlled without affecting the actual line-out program feed. Also called audio monitor.

*****

Production Schedule: The calendar that shows the reproduction, production, and postproduction dates and who is doing what, when, and where.

*****

System: The interrelationship of various elements and processes whereby the proper functioning of each element is dependent on all others.

*****

Feed: Signal transmission from one program source to another, such as a network feed or a remote feed.

To Be Continued In Next Issue-

Compilation:
Anmol

संपादक की कलम से

क्या है 5जी तकनीक ? क्या इस पर प्रतिबंध की मांग उचित है ?

4 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड की जानी–मानी अभिनेत्री जूही चावला की भारत में 5जी नेटवर्क लगाने के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका को खारिज करते हुए उन पर यह कहते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया कि याचिकाकर्ताओं ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। उल्लेखनीय है कि जूही चावला सहित दो अन्य याचिकाकर्ताओं वीरेश मलिक और टीना वाच्छानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 5जी तकनीक की टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े किए थे। याचिका में 5जी से संभावित खतरों का जिक्र करते हुए 2019 में बेल्जियम की पर्यावरण मंत्री सेलीन फ्रेमां के उस बयान का उल्लेख किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रसेल्स के लोग 'गिनी पिग' नहीं हैं, जिनके स्वास्थ्य को हम मुनाफे के लिए बेच दें और वह ऐसी तकनीक का स्वागत नहीं कर सकती, जिससे नागरिकों की सुरक्षा करने वाले रेडिएशन स्टैंडर्ड्स की इज्जत नहीं हो सकती, फिर चाहे वह 5जी ही हो।

याचिका में कहा गया कि इस मामले पर अध्ययन किया जाना चाहिए कि कहीं इस तकनीक के चलते इंसानों, जानवरों और प्रकृति को नुकसान तो नहीं हो रहा। याचिकाकर्ताओं ने करीब पांच हजार पन्नों वाली अपनी याचिका डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, आईसीएमआर, सीपीसीबी जैसी कुछ कई प्रमुख सरकारी एजेंसियों कुछ यूनिवर्सिटी तथा डब्ल्यूएचओ को पार्टी बनाते हुए अदालत से मांग की थी कि वह इन एजेंसियों को आदेश दे कि वे निष्पक्ष जांच करके पता लगाएं कि 5जी स्वास्थ्य के लिए कितना सुरक्षित है। याचिकाकर्ताओं के वकील दीपक खोसला ने अदालत से अनुरोध किया था कि 5जी तकनीक से गंभीर खतरे हैं, इसलिए इसे तब तक रोक दिया जाए, जब तक कि सरकार स्वयं पुष्टि न करे कि इससे कोई खतरा नहीं है। बहरहाल, अदालत द्वारा याचिका को दोषपूर्ण, अदालत का समय बर्बाद करने वाली और प्रचार पाने के लिए दायर की गई याचिका बताते हुए न केवल इसे खारिज कर दिया गया बल्कि याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंक दिया। अदालत की नाराजगी की वजह यह भी थी कि जूही चावला ने सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया पर शेयर किया था और कुछ अज्ञात लोगों ने उसी लिंक के जरिये तीन बार अदालती कार्यवाही के दौरान जूही चावला के गाने गाकर सुनवाई में व्यवधान उत्पन्न किया। इसलिए भी अदालत द्वारा सख्त शब्दों में कहा गया कि ऐसा लगता है कि यह याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी।

याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में कुछ ही ऐसी जानकारी हैं, जो सही हैं बाकी सिर्फ कयास ही लगाए गए हैं और संशय जाहिर किया गया है। दरअसल जब अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील से पूछा कि उन्होंने किस आधार पर यह संशय जाहिर किया और क्या इसे लेकर कोई जानकारी, स्टडी या रिपोर्ट है तो 'नहीं' में जवाब देते हुए दलील दी गई कि यही जानकारियां हासिल करने के लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उसी के बाद अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि अदालत उम्मीद करती है कि यदि अदालत में कोई याचिका दायर की जा रही है तो वह पूरे तथ्यों और जानकारी के साथ ही दायर हो, अदालत का समय बर्बाद करने के लिए नहीं।

जूही चावला की याचिका में कहा गया था कि यदि टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री की 5जी योजना सफल हो गई तो कोई भी व्यक्ति, जानवर, चिड़िया और यहां तक कि कोई पत्ता तक हर पल रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से बच नहीं सकेगा और इस रेडिएशन का स्तर आज के स्तर से 10 से 100 गुना ज्यादा होगा। हालांकि विश्व के कई अन्य देशों में भी लोग ऐसी चिंताएं जताते रहे हैं कि 5जी रेडिएशन का एक्सपोजर बढ़ने से कैंसर जैसी प्राणघातक बीमारियां तेजी से बढ़ सकती हैं लेकिन अभी तक के अधिकांश अध्ययनों में यही कहा गया है कि 5जी एंटीना से निकलने वाले रेडिएशन का स्तर कम होता है। दरअसल मोबाइल सिग्नल भेजने या रिसीव करने के लिए 5जी तकनीक को कई नए बेस स्टेशनों की जरूरत पड़ती है। इस तकनीक को पुरानी तकनीक के मुकाबले जमीन के नजदीक ज्यादा ट्रांसमीटर की जरूरत होती है और ज्यादा ट्रांसमीटरों का अर्थ है कि वे 4–जी तकनीक के मुकाबले कम बिजली पर चल सकते हैं अर्थात् एंटीना से निकलने वाले रेडिएशन का स्तर कम होता है। हालांकि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च द्वारा मोबाइल फोन से पैदा होने वाले इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इंसानों के लिए संभावित कैंसर पैदा करने वाला माना गया है लेकिन डब्ल्यूएचओ की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक इस संबंध में ऐसे कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिनसे साबित होता हो कि मोबाइल फोन से पैदा होने वाले इलैक्ट्रोमैग्नेटिग फील्ड से इंसानों में पक्के तौर पर कैंसर होता है। वैसे भी 5जी तकनीक को दूसरी सेल्युलर तकनीकों से अलग माना जाता है। दरअसल 5जी नेटवर्क रेडियो तरंगों पर आधारित सिग्नलों पर निर्भर होता है, जो एंटीना तथा मोबाइल फोन के बीच प्रसारित होती हैं। यह तकनीक पुराने मोबाइल नेटवर्क से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों का इस्तेमाल करती है, जिससे बहुत तेज इंटरनेट स्पीड के साथ एक साथ बहुत ज्यादा मोबाइल फोनों पर इंटरनेट सुविधा का आनंद लिया जा सकता है।

5जी तकनीक से मानव स्वास्थ्य पर क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, इसका खुलासा तो दुनियाभर में निष्पक्ष वैज्ञानिक अध्ययनों के बाद ही हो सकेगा लेकिन इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन के अध्ययनकर्ताओं का यह अवश्य कहना है कि 5जी रेडिएशन से निकलने वाली गर्मी नुकसान नहीं पहुंचाती। उनके मुताबिक अगर 5जी रेडिएशन से कोई व्यक्ति सर्वाधिक रेडियो फ्रीक्वेंसी से भी एक्सपोज हुआ होगा तो वह भी इतना कम होगा कि उससे आज तक तापमान बढ़ा हुआ नहीं पाया गया। बहरहाल, वर्ष 2020 में डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन 2022 में 5जी सहित सभी रेडियो फ्रीक्वेंसी के एक्सपोजर से स्वास्थ्य पर होने वाले खतरों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। उसके बाद ही यह खुलासा हो सकेगा कि 5जी रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं और है तो किस हद तक?

जहां तक 5जी तकनीक को लेकर जूही चावला की याचिका की टाइमिंग का सवाल है तो यह पूरी तरह गलत था। दरअसल पिछले कुछ समय से भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में 5जी तकनीक को कोरोना संक्रमण से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 5जी टेस्टिंग के कारण ही दुनियाभर में कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा है। ऐसी ही अफवाहों के चलते पिछले साल ब्रिटेन में लोगों द्वारा कुछ 5जी टावरों को आग लगा दी गई थी। इस समय भारत में 5जी पर ट्रायल चल रहे हैं जबकि क्रांतिकारी मानी जाने वाली यह तकनीक अमेरिका, यूरोप, चीन, दक्षिण कोरिया इत्यादि विश्व के कई देशों में पहले से ही काम कर रही है। यह तकनीक क्रांतिकारी इसलिए मानी जाती है क्योंकि 5जी से इंटरनेट की गति कई गुना तेज हो जाती है और इंटरनेट आधारित बड़े–बड़े कार्य भी बहुत तीव्र गति से डाटा ट्रांसफर होने के कारण पलक झपकते ही सम्पन्न हो जाते हैं। इससे रक्षा, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि लगभग सभी क्षेत्रों में क्रांति आ जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, टेली–सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी इत्यादि को ज्यादा विकसित करने में मदद मिलेगी।

International Yoga Day

Celebrated on June 21, International Yoga Day celebrates the physical and spiritual prowess that yoga has brought to the world stage. While it is an important source of exercise and healthy activity millions join in and practice on a daily basis. For many, these routines are a way to connect the body, mind and soul in a way that has existed for centuries.

HISTORY OF INTERNATIONAL YOGA DAY

For International Yoga Day, people around the world are all set to take out their yoga mats and start exercising, but they might not be aware that yoga goes back centuries. Yoga is considered to be an ancient practice that originated 5,000 years ago in India. Yoga was developed as a way to interconnect the mind, body and soul to step closer into enlightenment. As the practice became popular in the west, it became popularized as an exercise and relaxation method, with claims to help the body's general well-being, alleviate physical injuries and chronic pain.

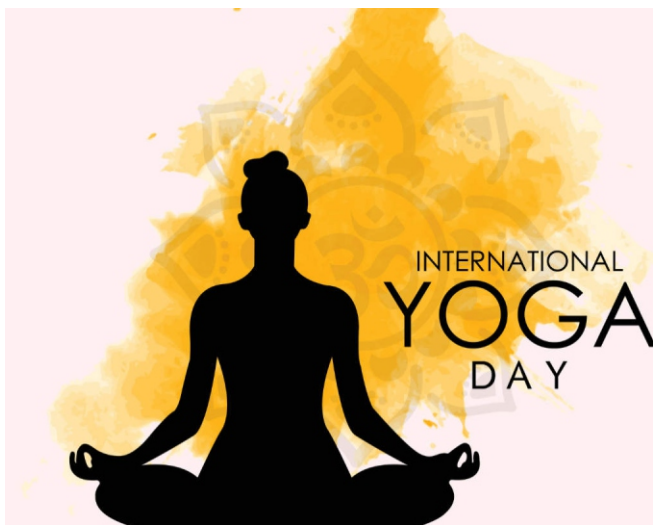

The idea of International Yoga Day was first proposed by Prime Minister Narendra Modi on September 27, 2014, during his speech at the UN General Assembly, where a resolution to establish June 21 as International Yoga Day was introduced by India's Ambassador, Asoke Kumar Mukerji.

The date of June 21 was chosen as it is the Summer Solstice, the day where there is the most sun out of every other day of the year. Overall, it received support from 177 nations, the highest number of co-sponsors for any UN resolution, proclaiming June 21 as the International Yoga Day.

On June 21, 2015, nearly 36,000 people, including Prime Minister Modi, and many other high-profile political figures from all around the world, performed 21 asanas (yoga postures) for 35 minutes in New Delhi in what was the first International Yoga Day, and the day has been celebrated around the globe ever since.

Parul, BAJMC, 3rd Year

सिर्फ चाय ही नहीं, इन रेसिपी में भी करें लेमनग्रास का इस्तेमाल, मिलेगा बेहतर स्वास्थ्य और स्वाद

जब लेमनग्रास का नाम आता है तो सबसे पहले लेमनग्रास टी पीने का ख्याल ही मन में आता है। हालांकि, लेमनग्रास का सेवन अन्य भी कई तरीकों से किया जा सकता है। यह एक हेल्दी इंग्रीडिएंट है जो अपने एंटी–माइक्रोबियल और एंटी–बैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है। यह लीवर, किडनी, ब्लैडर और अग्न्याशय को डिटॉक्सीफाई करने के लिए जाना जाता है। यह आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को कम करता है और मुंहासों को कम करके स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देता है। लेमन ग्रास में नींबू जैसा स्वाद होता है और इसका उपयोग चाय, सूप और करी में किया जाता है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है। थाई फूड करी में ताजा लेमन ग्रास का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसे सूखे या पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको लेमनग्रास को अलग–अलग रेसिपी में इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं–लेमन ग्रास आइस टी

लेमन ग्रास आइस टी अपने बेहतरीन स्वाद के साथ गर्मी के दिनों में आनंद लेने के लिए एक आदर्श पेय है। इसे बनाना बेहद सरल है और इसे बनाने में केवल 5 मिनट लगते हैं। बस, आपको एक गहरे नॉन–स्टिक पैन में 2 कप पानी, 1/4 कप चीनी, 1/4 कप लेमनग्रास और 2 टी–स्पून चाय पाउडर मिलाना है। सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिला लें और मध्यम आँच पर बीच–बीच में हिलाते हुए 6 मिनट तक पका लें। एक गहरे बाउल में छलनी से चाय को छान लें। इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। परोसने से ठीक पहले, 2 अलग–अलग गिलास में कुछ बर्फ के टुकड़े और 2 नींबू के टुकड़े डालें और प्रत्येक गिलास में आधा लेमनग्रास चाय का मिश्रण डालें, इसे हिलाएं और तुरंत परोसें।

ग्रीन करी थाई पेस्ट

यह एक ऑथेंटिंग थाई पेस्ट है जिसे ताजी हरी जड़ी–बूटियों और मसालों का उपयोग करके बनाया जाता है। यहां उपयोग की जाने वाली प्राथमिक सामग्री में से एक लेमनग्रास है जो थाई करी बनाने के लिए कई सब्जियों में स्वाद को कई गुना बढ़ाती है। आप इस पेस्ट का उपयोग थाई फ्राइड–राइस, टेबल–टॉप थाई करी आदि व्यंजनों के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आप करीबन डेढ़ बड़ा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन, 1/2 कप मोटा अदरक, 1 कप कटा धनिया, 1/2 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ नींबू, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1/2 कप कटा हुआ लेमनग्रास, नमक और काली मिर्च स्वादानुसार मिलाएं। अब इसमें कप पानी डालें और इन सभी सामग्रियों को मिक्सर में डाल दें। इसे अच्छी तरह मिला लें। एक एयरटाइट कंटेनर में या फ्रिज में स्टोर करें।

उडाको

गले में खराश और अपच को ठीक करने के लिए यह एक बहुत ही लोकप्रिय घरेलू उपाय है। प्राथमिक सामग्री लेमनग्रास है जो दूध, पुदीना और अदरक के साथ बीमारियों को ठीक करने में अपना जादू करती है। उडाको बनाने के लिए एक सॉस पैन में 1 कप दूध, 1/4 कप कटा हुआ लेमनग्रास, 2 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1/4 कप पुदीना की पत्तियां, 1 टेबलस्पून चीनी और 2 कप पानी मिलाएं। अब इन सबको अच्छी तरह मिला लें और मध्यम आँच पर बीच–बीच में हिलाते हुए 5 मिनट तक पका लें। मिश्रण को छलनी से छान लें और गरमागरम परोसें।

वंशिका सक्सेना, बीएजेएमसी तृतीय वर्ष

Vol. 14 **No.** 5
RNI No.: DEL/BIL/2004/14598
Publisher: Ram Kailsah Gupta on behalf of Tecnia Institute of Advanced Studies, 3 PSP, Madhuban Chowk, Rohini, Delhi-85; **Printer:** Ramesh Chander Dogra; **Printed at:** Dogra Printing Press, 17/69, Jhan Singh Nagar, Anand Parbat, New Delhi-5
Editor: Bal Krishna Mishra responsible for selection of News under PRB Act.
All rights reserved.

IMPORTANT QUOTES

"I do not consider it an insult, but rather a compliment to be called an agnostic. I do not pretend to know where many ignorant men are sure -- that is all that agnosticism means."

- Clarence Darrow

*****

"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal."

- Henry Ford

*****

"I'll sleep when I'm dead."

- Warren Zevon

*****

"There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread."

- Mahatma Gandhi

*****

Compilation: Anmol

WINNERS v/s LOOSERS Part-90

The Winner is always part of the answer;
the Loser is always part of the problem.

*****

Winners are always part of the solution;
Losers are always part of the problem.

*****

The Winner says, "Let me do it for you";
the Loser says, "That's not my job."

*****

Winners have dreams;
losers have schemes.

*****

A Winner in the end gives more than he takes.
A Loser dies clinging to the illusion that winning means taking more than you give.

To Be Continued In Next Issue-

Compilation: Vinayak

All Students and Faculty are welcome to give any Article, Feature & Write-up along with their Views & Feedback at: **youngstertias@gmail.com**